हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

निर्भीक, निष्पक्ष, सच का प्रवाह

वर्ष:5 अंक:55 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, रविवार, 01 मार्च 2026

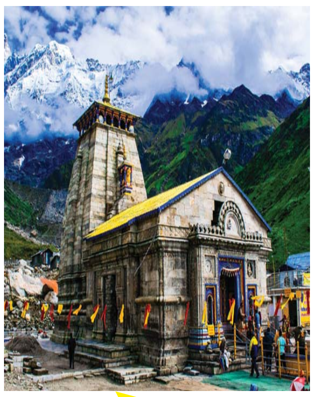

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

पथ प्रवाह, हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एफटीआई सभागार, हल्द्वानी में कानून व्यवस्था एवं जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं समन्वय के साथ पूरे किए जाएं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर प्रभावी रोक के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सभी संवेदनशील स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जाने, सोलर फेंसिंग व तारबाड़ प्रणाली को मजबूत करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को ठोस एवं कारगर उपाय अपनाने के लिए कहा, ताकि जनहानि और फसलों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

वनाग्नि की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने फायर लाइन (अग्निरोधक खाइयों) को दुरुस्त रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, रेंजवार मॉनिटरिंग करने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनाग्नि की किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विकास कार्यों में समन्वय और जवाबदेही पर जोर

हल्द्वानी शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, अतः निर्माण कार्यों के दौरान जनता को अनावश्यक असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और जवाबदेही के साथ करें। कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग आपसी जिम्मेदारियों को एक-दूसरे पर न डालें और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हों।

कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस, प्रशासन तथा सभी विभागों को आमजन के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए।

रानीबाग में आईटी हब की योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि रानीबाग स्थित बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की भूमि पर सरकार द्वारा आईटी हब विकसित करने की योजना पर कार्यवाही गतिमान है। इससे क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने हल्द्वानी नगर के बच्चीनगर सहित अन्य क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की नहरों के चौड़ीकरण एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सुझाव

सांसद अजय भट्ट ने वन क्षेत्रों में वाचरों की संख्या बढ़ाने, झाड़ियों की कटान करने तथा वन आच्छादित क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों की नियमित सफाई एवं मरम्मत कराने का सुझाव दिया। सचिव/आयुक्त दीपक रावत ने कुमाऊँ मंडल में कानून व्यवस्था, ओवरलोडिंग के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई तथा अन्य प्रशासनिक कदमों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पनियाली क्षेत्र में नियमित गश्त की जा रही है तथा ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से वन क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा क्षेत्र भीमताल के विभिन्न गांवों में 15 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार पनियाली क्षेत्र में भी 15 लाख रुपये स्वीकृत कर वितरित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं एवं पशुपालकों को चारा लेने के लिए जंगल न जाना पड़े। वन संरक्षक सी.एस. जोशी ने अवगत कराया कि पनियाली क्षेत्र में कैमरों में लैपर्ड नहीं, बल्कि बाघ की पहचान हुई है, जिसे पकड़ने की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत

पथ प्रवाह, देहरादून।

प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्पगुच्छ भेंट कर उत्तराखंड आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से समस्त कृषि उद्यमी अभ्यर्थी प्रशिक्षार्थी के संबंध में अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि प्रशिक्षार्थियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए पूर्ण किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस निर्णय से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षार्थियों के भविष्य, शैक्षणिक समय एवं उनके व्यावसायिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रशिक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम में समय, संसाधन एवं आशाओं के साथ सहभागिता की है, ऐसे में बैच निरस्तीकरण से उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि प्रशिक्षार्थियों के हितों, उनके उज्ज्वल भविष्य तथा शैक्षणिक समय को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलतापूर्वक पुनर्विचार कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को निरंतरता दी जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रशिक्षार्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में 200 से ज्यादा मौतें, धुआं-धुआं हुआ मिडिल ईस्ट

तेहरान। इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरानी राष्ट्रपति भवन सहित कई ठिकानों पर हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका सैन्य ठिकानों, तेल अवीव और इजरायल के अन्य स्थानों पर मिसाइल हमले किए. ईरान में अब तक इस हमले में 85 स्कूली छात्राओं समेत करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है. इजरायली हमले में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादेह और ढ्क्त्नष्ट के कुछ कमांडरों की मौत के दावे भी किए जा रहे हैं. इजरायल ने कहा कि इस ऑपरेशन की तारीख हफ्तों पहले तय की गई थी, जिसका मकसद ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना है. इस हमले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और राष्ट्रपति सुरक्षित हैं. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अमेरिका और इजरायल के हमलों में उसके 201 लोग मारे गए और 747 लोग घायल हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन लक्ष्य बताए. पहला- ईरानी नौसेना को खत्म करना, दूसरा- ईरान के मिसाइल उद्योग को नष्ट करना और तीसरा यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. ट्रंप ने संभावित अमेरिकी हताहतों की चेतावनी भी दी. हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जवाबी कार्रवाई विनाशकारी होगी. इजरायल और अमेरिका ने ईरान के तेहरान, तबरेज, करमनशाह, कॉम, कराज, इस्फहान पर हमला किया. तेहरान का आसमान हमले के बाद धुएं के गुबार से भरा रहा. इस हमले के जवाब में ईरान ने कतर में अल उदेइद एयर बेस, कुवैत में अल सालेम बेस, यूएई में अल धाफरा एयर बेस, बहरीन में यूएस 5वीं फ्लीट बेस, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, इजरायल के हाइफा और गैली शहरों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागे. फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, 'ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए. हमारे देशों में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों से बचे. ईरान अपने ही लोगों के खिलाफ की जा रही भयावह हिंसा और दमन को बंद करे.' फ्रांस, जर्मनी और यूके ने साफ किया कि वे इस हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और दूसरे अन्य देशों के संपर्क में हैं. बयान में कहा गया, 'हम क्षेत्र के देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. ईरान को अंधाधुंध सैन्य हमलों से बचना चाहिए. हम वार्ता को फिर से शुरू करने का आह्वान करते हैं और ईरानी नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि वह बातचीत के जरिए समाधान खोजे. अंततः ईरानी जनता को अपना भविष्य स्वयं तय करने की अनुमति मिलनी चाहिए.'

पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का शनिवार को आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और उनके इजरायली समकक्ष गिदोन सार के साथ फोन पर बातचीत की. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है.

एक नजर

आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की धूम

पथ प्रवाह, हरिद्वार। आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, बहादुरपुर जट में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न विज्ञान आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपने ज्ञान और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में नीलू ने प्रथम स्थान, अमन ने द्वितीय स्थान तथा युवराज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्र-छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विज्ञान अध्यापक एवं अध्यापिकाओं–शाहिद अली, छवि सैनी, कामेश कश्यप और आयुषी चौधरी–को भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने विज्ञान शिक्षकों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सी वी रमन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि डॉ. रमन को उनके अद्वितीय वैज्ञानिक योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव की खोज सहित उनके अनेक आविष्कारों ने विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने और वैज्ञानिक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं, बल्कि जीवन को समझने और समस्याओं का समाधान खोजने का माध्यम है। कार्यक्रम में विकास यादव, अनीता चौहान, वीर सिंह कश्यप, रिशिपाल यादव, अरुणा यादव, सुदेश चौहान, सतीश शास्त्री सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण बना रहा।

बिजली बिल जमा न करने वाले बकायेदारों के काटे कनेक्शन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में शनिवार को ऊर्जा निगम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 105 कनेक्शन काट दिए। इस दौरान मौके पर 14 लाख रुपये का राजस्व भी वसूला गया। ऊर्जा निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिल जमा कराने के लिए बार बार आग्रह करने के बाद भी जो उपभोक्ता बिजली के बकाया बिल जमा नहीं करा रहे थे उनके कनेक्शन काटे गए। बकायेदारों के खिलाफ अवर अभियंता अक्षय चौहान और मुकेश रवि के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। प्रथम-सब डिवीजन में 70 और द्वितीय-सब डिवीजन में 35 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। प्रथम सब डिवीजन से 11 लाख और द्वितीय सब डिवीजन से तीन लाख रुपये नगद जमा कराए गए।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस हरिद्वार-रुड़की द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। पिछले दस दिनों से चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 34 व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्यवाही की गई। साथ ही उनके वाहन सीज करते हुए संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय/जेल भेजा गया। आगामी त्योहारी सीजन (होली) के दृष्टिगत यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा। यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन न चलाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जनपद की सम्मानित जनता से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

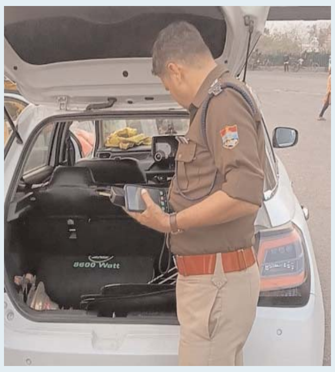

जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। स्थानीय उद्योगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उद्योग विभाग के राजकीय मिनी औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटियों/उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शैली डबराल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जनपद में विभाग के तीन मिनी औद्योगिक आस्थान क्रमशः गणेशपुर भटवाड़ी, सैणी डुण्डा तथा पुरोला में अवस्थित है। जिनमें से मिनी औद्योगिक आस्थान पुरोला अविकसित है एवं मिनी औद्योगिक आस्थान गणेशपुर भटवाड़ी व मिनी औद्योगिक आस्थान सैणी डुण्डा विकसित है जिनमें क्रमशः 21 भूखण्ड व 31 भूखण्ड है जो क्रमशः 13 व 09 उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा उद्यमियों को विधिवत रूप से औद्योगिक इकाइयों का संचालन करने तथा राज्य में मॉडल इकाई के रूप में स्थापित करने के निर्देश के साथ इकाई संचालन से संबंधित किसी भी समस्याओं के निस्तारण में सहयोग का आश्वासन दिया गया। उन्होंने लम्बे समय से अकार्यरत इकाइयों तथा अनुपस्थित उद्यमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्गत किए गए।

शांति और सौहार्द के साथ मनाएं त्योहार, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई: आशुतोष राणा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। होली और रमजान के दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में शांति समिति की बैठकें कर रही है। इस दौरान सम्भ्रान्त व्यक्तियों, सीएलजी मेम्बरों, क्षेत्रीय पार्षद आदि के साथ बैठक कर उनसे विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आगामी पर्वों को शान्तिपूर्ण माहौल में मनाने एवं शासन प्रशासन से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। शनिवार को एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर द्वारा आगामी त्यौहार होली एवं रमजान पर्व के दृष्टिगत सम्भ्रान्त व्यक्तियों, सी0एल0जी0 मेम्बरों, पार्षदों आदि के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें एसएसआई प्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी गैस प्लान्ट एसआई विकास रावत, चौकी प्रभारी सुमननगर एसआई अर्जुन कुमार व अन्य एसआई उपस्थित हुये। गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर हरिद्वार द्वारा उपस्थित सभी लोगों को होली व रमजान पर्व को शान्ति पूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस दौरान शासन/प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि होली, रमजान में हुडदंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों में आपराधिक घटनाऐं करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गयी। साथ ही उपस्थित लोगों से उक्त पर्वो के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस को सहयोग प्रदान करने की भी अपेक्षा की गयी।

शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने की बैठक

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी होली त्यौहार व प्रचलित रमजान महीने के दृष्टिगत सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण मनाये जाने के उद्देश्य से थाना बहादराबाद की शांतरशाह चौकी क्षेत्र में शांति समिति और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने बैठक की।

थाना बहादराबाद की चौकी शांतरशाह क्षेत्र में आगामी होली और ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गोष्ठी क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर संजय चौहान की अध्यक्षता आयोजित की गयी जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बहादराबाद चौकी प्रभारी शांतरशाह व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया।

क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर संजय चौहान ने सभी से अपील करते हुए कहा कि होली और ईद जैसे पवित्र पर्व आपसी भाईचारे और सद्भाव के प्रतीक हैं, इन्हें मिलजुलकर मनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का हुड़दंग, अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पर्वों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में यातायात व्यवस्था, जुलूस मार्ग, सुरक्षा प्रबंध और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपस्थित गणमान्य लोगों ने पुलिस प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

नाबालिग के अपहरण का इनामी आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली ज्वालापुर ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसएसपी द्वारा पांच हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक बीती 23 फरवरी को ज्वालापुर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज करायी कि नामजद आरोपी जावेद उसकी नाबालिग बेटी को बहका फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की? गिरफ्तार करने और अपहृता को सकुशल बरामद करने के लिए टीमों का गठन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा तत्काल नाबालिग बालिका की बरामदगी/आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को निर्देशित किया गया व अपहरण करने वाले नामजद आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 रुपये का ईनाम घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर द्वारा तत्काल नाबालिग बालिका की बरामदगी/ईनामी आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर टीमो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। टीमों द्वारा तत्काल वादिया के परिजनों से सम्पर्क कर मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रानिक माध्यम से आस पास जानकारी/पूछताछ कर मुखवीर ख़ास को क्षेत्र में सक्रिय किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/अन्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर गैर प्रांत/अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दविश दी गई। मुखवीर ख़ास की सूचना पर आरोपी आलम उर्फ जावेद पुत्र सफदर निवासी इक्कड खुर्द थाना पथरी जनपद हरिद्वार को हरि लोक तिराहे से इक्कड जाने वाले रास्ते से पकडा गया। नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर बाद आवश्यक कार्रवाई कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से की मुलाकात

पथ प्रवाह, खटीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा भ्रमण के दूसरे दिन शनिवार को कैंप कार्यालय लोहियाहेड तथा हेलीपेड परिसर में जनप्रतिनिधियों और आमजन से भेंट की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता और तत्परता बरती जाए तथा विकास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री फरजाना बेगम, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, महामंत्री रमेश चंद्र जोशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का किया शुभारंभ

पथ प्रवाह, हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद नैनीताल के हल्द्वानी भ्रमण के दौरान रामपुर रोड स्थित पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल एक अस्पताल के उद्घाटन का नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, संघर्ष और सेवा की प्रेरक यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ समाज के प्रति समर्पित एक ऐसे परिवार की कहानी को दर्शाता है, जिसने अपने जीवन मूल्यों को कर्म के माध्यम से साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने संस्थान के संस्थापक, जनपद बागेश्वर के गागरी गोल गांव से निकलकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले जगदीश सिंह पिमोली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एक साधारण ग्रामीण परिवेश से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा आज स्वास्थ्य सेवा के इस आधुनिक केंद्र तक पहुँची है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री पिमोली का संघर्ष, परिश्रम और संकल्प आज उनकी सफलता की सच्ची मिसाल है।

दूरस्थ गांव से आकर उन्होंने पहले व्यापार के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और अब चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश कर मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 250 बेड का यह आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित है। यह संस्थान भविष्य में चिकित्सा उत्कृष्टता के मानचित्र पर उत्तराखंड को और अधिक सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हमारी बेटियों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थी। बेटियों को इस गंभीर रोग से सुरक्षित करने के संकल्प के साथ यह राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ और प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 61 लाख से अधिक नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। ये सभी प्रयास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने 'विकल्प रहित संकल्प' को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया तथा सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में सांसद नैनीताल-ऊधमसिंह नगर अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक लालकुआं मोहन सिंह बिष्ट, विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, विधायक नैनीताल सरिता आर्या, विधायक कपकोट सुरेश गड़िया, मेयर हल्द्वानी गजराज सिंह बिष्ट, दायित्वधारी अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्या, शंकर कोरंगा, नवीन लाल वर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक जगदीश पिमोली एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

एचईसी कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन

पथ प्रवाह, हरिद्वार

एचईसी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन संदीप चौधरी एवं प्राचार्या डॉ. तृप्ति अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर चेयरमैन संदीप चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य छात्रों एवं आम जनमानस में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना तथा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों और नवाचारों की सराहना करते हुए इसे भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

छात्रों ने दिखाई वैज्ञानिक प्रतिभा

विज्ञान प्रदर्शनी में बीएससी, एमएससी, बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी), बीएससी (माइक्रोबायोलॉजी) तथा बीएससी ऑनर्स (एग्रीकल्चर) के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदर्शनी में

फोटोथेरेपी, नैनोटेक्नोलॉजी, माइक्रोग्रीन्स, मिनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक मॉडल जैसे आकर्षक और ज्ञानवर्धक विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने स्वयं निर्मित उत्पाद जैसे ऑर्गेनिक धूपबत्ती, रोज वॉटर, एलोवेरा सैनिटाइजर, लिप बाम आदि भी प्रदर्शित किए, जिन्हें दर्शकों ने काफी सराहा।

विजेताओं को किया गया सम्मानित

निर्णायक मंडल में डॉ. निधि जोशी, अशोक कुमार, मीनाक्षी, कुमारप्रीत एवं करुणा नेहरा शामिल रहे।

मॉडल प्रतियोगिता परिणामः
श्रेया एवं निशा के 'फोटोथेरेपी' मॉडल को प्रथम स्थान गरिमा श्रीवास्तव एवं विशाखा के 'नैनोटेक्नोलॉजी' मॉडल को द्वितीय स्थान कीर्ति भट्ट, आस्था एवं विश्रुत के 'मिनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक मॉडल' को तृतीय स्थान

प्रोडक्ट स्टॉल प्रतियोगिता परिणामः
भावना, गरिमा व अर्णव के 'धूपबत्ती' स्टॉल को प्रथम स्थान
हिमप्रीत, वंशिका सिंह एवं वंश के 'फेस मास्क' स्टॉल को द्वितीय स्थान
तनिष्का एवं प्रियांजली के 'प्रोबायोटिक' स्टॉल को तृतीय स्थान

इनोवेटिव आइडियाज श्रेणी में सिद्धार्थ को प्रथम स्थान, कासवी को द्वितीय स्थान मिला। विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन में विभागाध्यक्ष डॉ. पूजा मिश्रा, डॉ. निधि जोशी, डॉ. दीपिका संगतानी, अंजली विश्नोई, अशोक कुमार, डॉ. तनु चंद्रा, डॉ. निधि वर्मा, मीनाक्षी सिंघल, कुमारप्रीत सहित समस्त शिक्षकगण की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। यह प्रदर्शनी न केवल विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच बनी, बल्कि उपस्थित जनसमूह के लिए भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी सिद्ध हुई।

बेटियों की सेहत का राष्ट्रीय सुरक्षा कवचः एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

देशभर में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान की आधिकारिक शुरुआत अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने के बाद जनपद उत्तरकाशी में भी शनिवार से इसका विधिवत शुभारंभ हो गया। यह विशेष अभियान 31 मई तक संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुरेश चौहान गंगोत्री तथा प्रशांत आर्य जिलाधिकारी ने किया।

7 बालिकाओं को ये टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बी0एस0रावत ने बताया कि एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है और समय पर टीकाकरण से इस बीमारी से प्रभावी बचाव

संभव है। इस अभियान के अंतर्गत जनपद में 7 स्थानों पर ये टीका लगवाया जाएगा जिसमें सभी ब्लॉक मुख्यालय के चिकित्सालय तथा जिला चिकित्सालय शामिल है। जनपद में लगभग 3000 बालिकाओं को ये टीका लगाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ बी0एस 0पांगती ने कहा कि सभी सेशन स्थलों पर कोल्ड चेन व्यवस्था, प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक चिकित्सीय प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख अधीक्षक डॉ पीएस पोखरियाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कुलवीर राणा, डॉक्टर शैलेंद्र बिजलवाण ए0डी0आई0ओ0 प्रीति गौड़ सेमवाल और संजय बिजलवान, डीपीएम हरदेव राणा उपस्थित रहे।

पार्षद सुमित त्यागी ने जन्मदिन पर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए दो नई गाड़ियों का तोहफा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

नगर निगम हरिद्वार के वार्ड संख्या 58, राजा गार्डन के पार्षद एडवोकेट सुमित त्यागी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रवासियों को स्वच्छता का विशेष उपहार दिया। पार्षद ने वार्ड में डोर-टू-डोर घरेलू कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दो नई कचरा संग्रहण गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। इस पहल के तहत अब वार्ड के प्रत्येक घर, किरायेदारों और दुकानों से नियमित रूप से डोर-टू-डोर कचरा उठाया जाएगा। इससे क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी होने की उम्मीद है। पार्षद एडवोकेट सुमित त्यागी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर वार्ड में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की स्वच्छता नीति के अंतर्गत न्यूनतम यूजर चार्ज लागू किया जाएगा, ताकि सेवा का संचालन नियमित और

व्यवस्थित रूप से किया जा सके।

जनता से की विशेष अपील

पार्षद ने वार्डवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक अपना कचरा केवल कचरा संग्रहण गाड़ी में ही डालें। सार्वजनिक स्थानों, खाली प्लॉटों या सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वार्ड और स्वच्छ हरिद्वार बनाने में जनता की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। यदि सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो वार्ड 58 को स्वच्छता के मामले में एक आदर्श वार्ड बनाया जा सकता है। क्षेत्रवासियों ने भी पार्षद की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया और स्वच्छता अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

संपादकीय

सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार: व्यवस्था पर चोट

सरकारी महकमे किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की कार्यकारी शक्ति होते हैं। नीतियों का निर्माण भले ही राजनीतिक स्तर पर होता हो, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र पर होती है। ऐसे में यदि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पनपता है, तो उसका सीधा असर जनता के अधिकारों और देश के विकास पर पड़ता है। दुर्भाग्यवश, भारत में समय-समय पर सामने आए मामलों ने यह संकेत दिया है कि व्यवस्था के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखाई देता है। कभी फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत ली जाती है, तो कभी ठेकों और निविदाओं में कमीशनखोरी होती है। नियुक्तियों और तबादलों में लेन-देन की शिकायतें भी आम हैं। बड़े स्तर पर हुए घोटालों–जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति से जुड़ा विवाद या 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण–ने यह दर्शाया कि जब निगरानी कमजोर पड़ती है, तो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग संभव हो जाता है। हालांकि इन मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया चली, परंतु इससे व्यवस्था की छवि को जो क्षति पहुंची, उसकी भरपाई आसान नहीं है।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन या आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे जनता के मन में अविश्वास और हताशा की भावना जन्म लेती है।

सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (छ्व्क्ष) और सूचना का अधिकार (ऋञ्जद्ध) जैसे कदमों ने भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगाया है। तकनीक ने बिचौलियों की भूमिका कम की है और पारदर्शिता बढ़ाई है। लेकिन केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। जब तक प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी और दोषियों को त्वरित एवं सख्त दंड नहीं मिलेगा, तब तक सुधार अधूरा रहेगा।

आवश्यक है कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता मिले, सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा दिया जाए और व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों और सेवा भावना को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि नैतिक पतन का प्रतीक है। यदि सरकारी महकमों में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, तो न केवल जनता का विश्वास लौटेगा, बल्कि विकास की गति भी तेज होगी। मजबूत और निष्पक्ष प्रशासन ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।

दम है, तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाएं, मोदी

सनत जैन

सीबीआई के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज का निर्णय दिया है। निर्णय में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में आबकारी नीति घोटाले के मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, बिना सबूत के आरोपियों को आपराधिक मुकदमे में घसीटना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आपराधिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल जांच एजेंसी द्वारा किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, न्यायिक जांच की कसौटी पर अभियोजन पक्ष जरा भी नहीं टिक पाया। कोर्ट ने आरोपियों को फंसाने के लिए व्यापक साजिश के दावे की पुष्टि की है। जो सीबीआई के लिए सबसे बड़ा झटका है। अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को पूर्व नियोजित और कोरियोग्राफड बताते हुए गंभीर टिप्पणी की है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा, आपराधिक मुकदमे में इस तरह से किसी को भी नहीं उलझा सकते हैं। राजनीतिक असहमति को आपराधिक मामलों के रूप में प्रस्तुत करने की कोर्ट ने तीव्र आलोचना फैसले में की है। उल्लेखनीय है, जांच एजेंसी ने साउथ लावी के नाम से तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी कविता को 165 दिन तक हिरासत में रखा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अकारण 181 दिनों तक जेल में बंद करके रखा गया था। इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने फैसले में उत्तर और दक्षिण के बीच में राजनीतिक विद्वेष फैलाने का कृत्य माना है। न्यायालय ने आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह को आरोपी नंबर एक बनाने पर कड़ी आपत्ति फैसले में दर्ज की है। सीबीआई ने जिस तरह से आबकारी नीति को जबरिया अपराध साबित करने के लिए एक के बाद एक कई लोगों को फंसाती चली गई। संदिग्ध गवाह बनाए गए। काल्पनिक सबूत बयान के आधार पर तैयार करने की कोशिश की गई। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई के अधिकारियों ने जांच करते हुए चुनाव प्रचार, होटल बुकिंग, और भुगतान इत्यादि की जांच की। चुनाव आयोग के अधिकारों का उपयोग सीबीआई ने किया है। अधिकारियों ने संविधानिक सीमाओं को पार किया है। जिन लोगों ने पैसे लेने और देने के आरोप स्वीकार किए थे। सीबीआई ने उन्हें गवाह बना लिया। उन गवाहों के बयान पर अन्य लोगों को फंसाया गया। अदालत ने फैसले में कहा अभियोजन के बयान की कॉपी अदालत को नहीं मिली। रिकॉर्ड को देखने से पता लगता है, जांच एजेंसी ने अदालत को भी दृग भ्रमित किया है। ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से सारे मामलों का विवेचन करते हुए सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, उसके बाद केंद्र सरकार, जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी द्वारा चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को प्रभावित किया गया है। इस सभी कार्यवाही का लाभ भाजपा को मिला। उसको लेकर देश में एक नया दबाव सत्ता पक्ष और जांच एजेंसियों के ऊपर पडना शुरू हो गया है। कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सियासी षड्यंत्र था। उनकी पार्टी के पांच बड़े नेताओं को चुनाव के पहले जेल में बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज कर आम आदमी पार्टी को बदनाम कर चुनाव लड़ने से रोकने का हर संभव प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में मोदी और शाह को चुनौती देते हुए कहा, यदि भाजपा में दम है, तो दिल्ली विधानसभा और लोकसभा का दोबारा चुनाव कराएं। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी और सभी विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। सीबीआई और ईडी द्वारा जिस तरह से विपक्षी राजनेताओं को निशाने पर लिया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं को आपराधिक मामले में फंसाया गया है। चुनाव के ठीक पहले दोनों एजेंसियां सीबीआई, ईडी और बाद में इसमें इनकम टैक्स भी शामिल हो गया था। पूरी तरह से सरकार के दबाव में विपक्षियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे। इस फैसले के बाद अब विपक्ष को नई संजीवनी मिल गई है। सत्ता पक्ष के लिए भविष्य में कानून और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना आसान नहीं होगा। अभी तक विपक्षी दल दबाव में थे। अब विपक्ष पूरी तरह से मुखर हो चुका है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जो विशेष अधिकार मिले थे, पिछले कई वर्षों से उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सत्ता पक्ष के लिए हो रहा था।

आबकारी नीति मामले में आप नेताओं का बरी होना बड़ी संजीवनी

ललित गर्ग

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित आबकारी नीति प्रकरण में आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा अन्य आरोपितों को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय समकालीन राजनीतिक और विधिक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अर्थात सीबीआई द्वारा पंजीकृत किया गया था और लंबे समय से सार्वजनिक बहस के केंद्र में था। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप ठोस साक्ष्यों और विश्वसनीय गवाहियों पर आधारित नहीं हैं तथा आरोपपत्र में वर्णित दावे न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। न्यायालय की यह टिप्पणी कि अनुमानों और अटकलों को विधिसम्मत प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, न केवल इस विशेष प्रकरण बल्कि समग्र अन्वेषण प्रक्रिया के लिए भी गंभीर संकेत देती है। आबकारी नीति मामले यह फैसला आप के लिए एक बड़ी संजीवनी या 'प्राणवायु'के समान है। यह फैसला आप को 'कट्टर ईमानदार' की छवि वापस पाने और आगामी चुनावों के लिए एक आक्रामक रुख अपनाने में मदद करेगा, जिससे विपक्षी दलों का मनोबल भी बढ़ा है। कोर्ट से मिली क्लीन चिट ने आप नेताओं की साख बहाल की है जिससे पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यह निर्णय 'राजनीतिक प्रतिशोध' के नैरेटिव को बल देता है जिससे आप अपनी छवि को बेदाग साबित कर पा रही है। विपक्षी दल इस घटना को केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई एवं ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक जीत के रूप में देख रहे हैं जिससे उन्हें केंद्र के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस फैसले से दिल्ली और पंजाब में आप को मजबूती मिलेगी और वह आगामी चुनावों के लिए आक्रामक प्रचार कर सकती है। विवाद का मूल वर्ष 2021 में लागू की गई नई आबकारी नीति से जुड़ा था। उस समय दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि शराब व्यापार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से राजस्व में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। किंतु नीति के क्रियान्वयन के बाद उस पर अनियमितताओं तथा कथित पक्षपात के आरोप लगाए गए। यही आरोप आगे चलकर आपराधिक प्रकरण का आधार बने। जुलाई 2022 से यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय बन गया और चुनावी सभाओं में इसे व्यापक रूप से उठाया गया। अब जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों को अपर्याप्त पाया है, तो स्वाभाविक है कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय, में चुनौती देने की घोषणा की है। अतः अंतिम विधिक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं मानी जा सकती। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात ईडी ने यह कहा है कि उससे संबंधित धनशोधन प्रकरण की जांच स्वतंत्र आधारों पर चल रही है। यदि उच्च न्यायालय भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि समान घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न अन्वेषणों की विधिक संगति किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्वेषण एजेंसियों की भूमिका अत्यंत संवेदनशील होती है। वे केवल अपराध की जांच ही नहीं करतीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। यदि न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि जांच पूर्वनिर्धारित दिशा में चलती प्रतीत होती है या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत शुचिता पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। न्याय का मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष विधिसम्मत प्रमाणों के आधार पर सिद्ध न हो जाए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शासन की समग्र विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो कठोर दंड आवश्यक है; किंतु यदि आरोप पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में टिक नहीं पाते, तो इससे राजनीतिक विमर्श की विश्वसनीयता पर भी आघात पहुँचता है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, किंतु आरोपों का उपयोग यदि मुख्यतः चुनावी रणनीति के रूप में किया जाता है और वे न्यायालय में प्रमाणित नहीं हो पाते, तो इससे जनता के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस निर्णय के बाद स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी को नैतिक बल प्राप्त हुआ है। किंतु इस तथ्य को केवल किसी एक दल की विजय या पराजय के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इससे व्यापक स्तर पर यह संदेश भी जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र है और वह अभियोजन की कमजोरी को रेखांकित करने से संकोच नहीं करती। न्यायालय की कठोर टिप्पणियाँ यह संकेत देती हैं कि केवल आरोपों की गंभीरता पर्याप्त नहीं है; उन्हें प्रमाणों की दृढ़ता से पुष्ट करना भी अनिवार्य है। दूसरी ओर, यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि वास्तव में किसी नीति में अनियमितता हुई थी, तो उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं किए जा सके। क्या अन्वेषण प्रक्रिया में तकनीकी कमियाँ रहीं? क्या साक्ष्य-संग्रह में सावधानी का अभाव था? या फिर आरोपों का प्रारूपण ही पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? ये प्रश्न केवल इस प्रकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य की जांच प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। भ्रष्टाचार-निरोध की दिशा में प्रभावी कदम तभी संभव हैं जब अन्वेषण निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत हो। राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार-विरोध का नैतिक आग्रह तभी प्रभावी है जब वह स्वयं प्रमाण-आधारित हो। यदि आरोपों का आधार कमजोर होगा, तो वे न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं पाएंगे और इससे वास्तविक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष भी कमजोर पड़ेगा।

बोतलबंद पानी का भारत: सार्वजनिक जल प्रशासन की गहरी विफलता

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में बोतलबंद पानी पर बढ़ती निर्भरता केवल उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जल प्रशासन में व्याप्त गहरी और बहुस्तरीय प्रणालीगत समस्याओं की ओर भी स्पष्ट संकेत करती है। कभी जो नल का पानी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वही आज अविश्वास, असुरक्षा और असमानता का प्रतीक बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

आधुनिक भारत में जल संकट को अक्सर वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन या बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बोतलबंद पानी की लोकप्रियता का मूल कारण इनसे कहीं अधिक गहरा है। असल समस्या यह है कि नागरिकों का भरोसा सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणालियों से लगातार टूटता जा रहा है। नलों से आने वाले पानी की गुणवत्ता पर संदेह, नियमित आपूर्ति का अभाव, और पारदर्शिता की कमी ने लोगों को वैकल्पिक स्रोतों की ओर धकेल दिया है। जब राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, तब बाजार उस खाली स्थान को भर देता है–अक्सर मुनाफे की शर्तों पर।

शहरी भारत में बोतलबंद पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो यह लगभग जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी बड़े जार और बोतलें आम दृश्य हैं। यह स्थिति विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शहरों में सबसे विकसित जल अवसंरचना होने का दावा किया जाता है। यदि इतनी सुविधाओं के बावजूद नागरिक सुरक्षित नल का पानी नहीं पी सकते, तो यह प्रशासनिक विफलता का सीधा प्रमाण है। पाइपलाइन की जर्जर हालत, सीवेज और पेयजल लाइनों का आपस में मिलना, तथा नियमित परीक्षण की कमी–ये सभी समस्याएँ वर्षों से ज्ञात हैं, लेकिन समाधान आधे-अधूरे ही रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग होते हुए भी उतनी ही चिंताजनक है। वहां बोतलबंद पानी का उपयोग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जैसे-जैसे ग्रामीण बाजारों तक निजी कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है, यह निर्भरता वहां भी बढ़ने लगी है। कई इलाकों में भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक या आयरन की अधिकता के कारण लोग स्थानीय जल स्रोतों से डरने लगे हैं। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सामुदायिक नल या हैंडपंप अक्सर या तो खराब रहते हैं या फिर उनका पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में जिनके पास आर्थिक क्षमता है, वे बोतलबंद पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब तबके दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। यह स्थिति जल के क्षेत्र में गहरी असमानता को जन्म देती है।

बोतलबंद पानी उद्योग का विस्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक ओर यह उद्योग 'शुद्धता' और 'सुरक्षा' का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन में गंभीर खामियां हैं। कई बार यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध बोतलबंद पानी भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद उपभोक्ता इसे नल के पानी से अधिक सुरक्षित मानते हैं। यह धारणा स्वयं में सार्वजनिक जल संस्थानों की साख पर सवाल है। यदि राज्य द्वारा प्रमाणित और नियंत्रित जल आपूर्ति प्रणाली पर नागरिक भरोसा नहीं करते, तो यह लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए भी खतरे की घंटी है।

पर्यावरणीय दृष्टि से बोतलबंद पानी पर निर्भरता अत्यंत विनाशकारी है। प्लास्टिक की बोतलें कचरे के पहाड़ में बदल रही हैं। पुनर्चक्रण की दर बेहद कम है और अधिकांश प्लास्टिक अंततः नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा, बोतलबंद पानी के उत्पादन में भी भारी मात्रा में जल और ऊर्जा की खपत होती है। यानी जिस संसाधन की कमी की बात की जा रही है, उसी का अत्यधिक दोहन करके एक कृत्रिम समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विरोधाभास नीति निर्माताओं की अल्पकालिक सोच को उजागर करता है।

सार्वजनिक जल प्रशासन की समस्याएँ केवल तकनीकी नहीं हैं; वे संस्थागत और राजनीतिक भी हैं। जल प्रबंधन से जुड़े विभाग अक्सर संसाधनों की कमी, कुशल मानवबल के अभाव और आपसी समन्वय की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवा को राजनीतिक प्राथमिकता भी अक्सर नहीं मिलती। चुनावी घोषणाओं में बड़े बांध, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं या स्मार्ट शहरों की बातें तो होती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जल आपूर्ति को सुधारने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं वर्षों तक अनसुलझी रहती हैं।

निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भी इस संकट को गहरा कर रही है। जब सार्वजनिक प्रणालियाँ कमजोर होती हैं, तो समाधान के रूप में निजी कंपनियों को आगे लाया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इससे दक्षता बढ़ी है, लेकिन अक्सर इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो भुगतान कर सकते हैं। पानी जैसे आवश्यक संसाधन का बाजार आधारित वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। बोतलबंद पानी इस निजीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्वच्छ पानी एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता वस्तु बन जाता है।

इस पूरी स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बोतलबंद पानी पर निर्भरता धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। लोग इसे समस्या के लक्षण के बजाय समाधान के रूप में देखने लगे हैं। इससे सार्वजनिक दबाव कम होता है और प्रशासनिक सुधार की मांग कमजोर पड़ जाती है। जब नागरिक स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, तो राज्य पर जवाबदेही का दबाव घट जाता है। यह चुपचाप स्वीकार की गई असफलता भविष्य में और बड़े संकटों को जन्म दे सकती है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत भाजपा की कार्यशाला

पथ प्रवाह, हरिद्वार

भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति उत्तराखंड के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने की, जबकि संचालन भाजपा नेत्री अन्नू कक्कड़ द्वारा किया।

कार्यशाला का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के बैनर तले किया गया, जिसका उद्देश्य पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक स्पष्टता को सुदृढ़ करना और संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत बनाना रहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि भाजपा राष्ट्र सर्वोपरि, सुशासन और समग्र मानव दर्शन के आदर्शों से प्रेरित होकर एक आत्मनिर्भर, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल दर्शन अंत्योदय पर आधारित है–अर्थात पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान का संकल्प। उन्होंने विकेंद्रीकृत प्रयासों, सक्रिय जनभागीदारी और संवेदनशील स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से शासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम करने पर बल दिया।

नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित यह अभियान विकास के लाभों को समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचाने के संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं और कार्यकर्ताओं को जमीनी समस्याओं की बेहतर समझ प्रदान करते हैं।

जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ता विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पार्टी बूथ और मंडल स्तर की संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रशिक्षण अभियान को मंडल स्तर तक ले जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशिक्षित और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यकर्ताओं के बल पर केंद्र और राज्य में निरंतर सशक्त भूमिका निभा रही है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि कार्यशाला ने स्थानीय चुनौतियों के समाधान हेतु संवाद, फीडबैक और रणनीतिक योजना का प्रभावी मंच प्रदान किया। उन्होंने जनता से संवाद को और मजबूत करने तथा पार्टी इकाइयों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।

कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम सत्र में स्वागत उपरांत वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। द्वितीय सत्र में जिला अध्यक्ष एवं मंचासीन अतिथियों ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ बैठक कर मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार की तथा सभी मंडलों के कार्यक्रमों की तिथि एवं स्थान निर्धारित किए।

इस अवसर पर हरिद्वार किरण जैसल, राज्य मंत्री डॉ. जयपाल चौहान, पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार, संदीप गोयल, विकास तिवारी, ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी, महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, निपेंद्र चौधरी, आशु चौधरी, संदीप अग्रवाल, तरुण नैय्यर, सीमा चौहान, रीता चमोली, योगेश चौहान, संजीव कुमार, अजय गुप्ता, विक्रम भुल्लर, राजबीर कश्यप, तेलूराम प्रधान, प्रीति गुप्ता, अभिनव चौहान, लोकेश पाल, जसवीर बसेड़ा, एजाज हसन, रितु ठाकुर, नकली राम सैनी, विनीत जोली, धर्मेंद्र चौहान, लक्ष्मण सिंह नागर, संदीप शर्मा, विक्रम चौहान, विवेक चौहान, प्रमोद चौहान, मोहित वर्मा, प्रणव यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एक नजर

होली पर जनपद में देशी विदेशी मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रंगों के पर्व होली पर जनपद में सभी देशी विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश जारी कर दिये हैं। यह आदेश होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किये गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 4 मार्च को होली पर्व के अवसर पर जनपद में देशी विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को मदिरा की बिक्री परिवहन एवं उपभोग हेतु शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से सांय 05:00 बजे तक बन्द रखा जाएगा। उक्त बन्दी के फलस्वरूप 'होली' के अवसर पर जनपद मे सचालित सभी अनुज्ञापनो को बन्दी दिवस के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित / व्यवस्थापित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति / छूट देय नहीं होगी। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट,सभी उप जिलाधिकारियों, जिला आबकारी अधिकारी,समस्त आबकारी निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।

अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी को दी गई भावभीनी विदाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार। अधिवर्षता आयु पुर्ण करने पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी को विदाई समारोह कार्यक्रम जहां फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया वहीं उन्हें भावभीनी विदायी दी गई। जिलाधिकारी और एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री नेगी की भगवान से दीर्घ आयु की कामना की। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उन्हें सेवानिवृत्त होने पर शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि श्री नेगी सौम्य एवं सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है तथा उन्होंने 32 वर्ष की प्रशासनिक सेवा बाखूबी निभाया है तथा श्री नेगी ने दायित्वों का निर्वाहन बड़ी कुशलता एवं ईमानदारी से किया है तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।उन्होंने उनके सेवानिवृत्त के बाद का समय परिवार संग सुखी जीवन एवं दीर्घ आयु के लिए मां गंगा से प्रार्थना की।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने उन्हें सेवानिवृत्त होने की बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि श्री नेगी ने अपने 32 वर्ष की सेवा निर्विघ्न एवं कुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाहन किया है तथा उन्होंने श्री नेगी के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पी आर चौहान रावत,सचिव एचआरडीए मनीष कुमार, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी मीरा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष वर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री नेगी को उनके सेवानिवृत्त की बधाई एवं शुभकामना दी। कार्यक्रम का संचालन प्रशानिक अधिकारी नवीन मोहन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार, उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, जिला खनन अधिकारी काजिम रजा, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी सुदेश कुमार सहित जिला कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

होली पर हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की कड़ी नजर, कनखल पुलिस ने की ने शांति समिति की बैठक

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आगामी होली एवं रमजान पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह रावत ने शांति समिति की गोष्ठी आयोजित की गई। क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों, सीएलजी (कम्युनिटी लायजनिंग ग्रुप) सदस्यों, पार्षदों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

बैठक में कनखल, जमालपुर कलां, किशनपुर, जियापोता और जगजीतपुर क्षेत्र के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रभारी निरीक्षक ने सभी उपस्थितजनों को होली और रमजान पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए उनके पालन का आग्रह किया गया।

गोष्ठी के दौरान पुलिस और जनता के बीच आपसी समन्वय को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उपस्थित लोगों से पूर्व में आयोजित होली पर्व के अनुभवों के आधार पर सुझाव लिए गए तथा आगामी पर्व को और बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। प्रभारी निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि होली और रमजान के दौरान हुड़दंग करने वालों, असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों से भी अपील की गई कि वे पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि दोनों प्रमुख पर्वों को लेकर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और सतर्कता बरती जाएगी, जिससे सभी नागरिक आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मना सकें।

चारधाम यात्राः आरटीओ प्रशासन ने की टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक, बाहरी प्रदेशों के टैक्सी चालकों पर कसेगी लगाम

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में शनिवार को एआरटीओ कार्यालय हरिद्वार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरटीओ (प्रशासन), देहरादून संदीप सैनी द्वारा की गई। बैठक में जनपद हरिद्वार व रुड़की से संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यात्री-हितैषी बनाना था। बैठक में ट्रैवल्स एसोसिएशन हरिद्वार, पंचपुरी टेम्पो ट्रैवल यूनियन हरिद्वार, टैक्सी-मैक्सी यूनियन, लक्सर बस यूनियन एवं लक्ज़री कोच यूनियन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विशेष रूप से ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड एवं यात्रा पंजीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में एआरटीओ (प्रशासन) हरिद्वार निखिल शर्मा, एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा, एआरटीओ (प्रशासन) रुड़की जितेंद्र चंद एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) रुड़की कृष्ण पलारिया उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत जनपद में संचालित ई-रिक्शा सत्यापन (Verification) प्रक्रिया एवं क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंजीकृत वाहनों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने तथा अवैध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था एवं पर्यटन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं परिवहन संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी यूनियनों एवं अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करने की अपेक्षा की।

यूनियनों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदुः

1. हरिद्वार में भी ऋषिकेश की तर्ज पर 24 घंटे का यात्रा पंजीकरण कैंप संचालित किए जाने का प्रस्ताव।
2. बाहरी राज्यों के वाहनों द्वारा उत्तराखंड से सवारी उठाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किए जाने की मांग।
3. अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा।

बैठक में अवगत कराए गए महत्वपूर्ण बिंदुः

1. ट्रिप कार्ड निरस्तीकरण (Cancellation) प्रक्रिया को सरल किया जा चुका है, जिससे वाहन स्वामियों एवं चालकों को सुविधा प्राप्त होगी।
2. नवीन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट नियमों के अनुसार अब वाहन अपने गृह राज्य से ही संचालन प्रारंभ कर सकेंगे।
3. चारधाम यात्रा के दौरान प्रत्येक चेकपोस्ट पर जाँच के स्थान पर केवल उनियाल चेकपोस्ट पर आवश्यक सत्यापन किया जाएगा, जिससे यातायात सुचारू एवं निर्बाध बना रहे।
4. हरिद्वार में 24 घंटे पंजीकरण कैंप के संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित ओपन जिम का किया लोकार्पण

पथ प्रवाह, हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान, लोहियाहेड में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सौजन्य से निर्मित ओपन जिम का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में खेल और फिटनेस से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान, लोहियाहेड में आयोजित स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारम्भ किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी अत्यंत आवश्यक है। खेलों से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है तथा अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर संकल्प और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें करियर की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से खेलों के बुनियादी ढांचे को सशक्त किया गया है। परिणामस्वरूप हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है और अब हमारी देवभूमि खेलभूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 28 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है और इस वर्ष 10 हजार युवाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ओपन जिम उपकरणों का अवलोकन कर स्वयं व्यायाम किया तथा क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री फरजाना बेगम, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, महामंत्री रमेश चंद्र जोशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी सहित स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रुचि अग्रवाल, डॉ. विवेक अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, शिप्रा अग्रवाल, कॉलेज के विद्यार्थी एवं क्षेत्रीय जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भारत सरकार के एजेंडे के अनुरूप हो प्रस्तुतीकरण की तैयारी: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण भारत सरकार के एजेंडे के अनुरूप, अद्यतन आंकड़ों पर आधारित तथा परिणामोन्मुखी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की उपलब्धियों, नवाचारों और भावी कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाए, ताकि राज्य की शिक्षा क्षेत्र में प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रूप से रखा जा सके।

उच्च शिक्षा पर विशेष फोकस

समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालयों में तैनात फैकल्टी, छात्र संख्या, आधारभूत संरचना, पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों, इंटरनेट सुविधाओं, प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनों का विस्तृत और अद्यतन विवरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किए गए पाठ्यक्रम सुधारों, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनुरूप क्रेडिट संरचना, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, छात्रावास सुविधाओं तथा नवाचार आधारित पहलों को प्रस्तुतीकरण में प्रमुखता से शामिल करने को कहा।

विद्यालयी शिक्षा के लिए समयबद्ध लक्ष्य

विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए डॉ. धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि 8 मार्च तक सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा 1 अप्रैल तक प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने राजकीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था एवं आईसीटी लैब निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे से संबंधित प्रस्ताव को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

बालिका शिक्षा और नामांकन दर पर जोर

मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आगामी राष्ट्रीय बैठक के लिए तैयार किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण में बालिका शिक्षा पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (त्रश्वक्र), भारत दर्शन कार्यक्रम, जॉब फेयर, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, निपुण भारत मिशन, निपुण विद्यालय कार्यक्रम, आदर्श विद्यालय योजना तथा अन्य नवाचारी पहलों को प्रमुखता से शामिल करने को कहा। बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक मुकुल कुमार सती, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा आनंद सिंह उनियाल, उप निदेशक दीपक पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नयार वैली फेस्टिवल ने नयार घाटी को दी राष्ट्रीय पहचान

पथ प्रवाह,पौड़ी

तीन दिवसीय नयार वैली फेस्टिवल के अंतिम दिवस विभिन्न साहसिक खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के साथ उत्साह, रोमांच और उल्लास के वातावरण में कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी तथा जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

विधायक ने समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों, आयोजकों, विभागीय अधिकारियों, स्वयंसेवकों तथा स्थानीय नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक प्रतिभागी बधाई का पात्र है, क्योंकि साहसिक खेलों में भागीदारी स्वयं में साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीत केवल पदक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह निरंतर अभ्यास, समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम होती है।

विधायक ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को साहसिक खेलों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पर्वतीय भू-भाग को देखते हुए उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और पेशेवर अवसरों की दिशा भी मिलती है।

उन्होंने कहा कि नयार घाटी जैसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। जब स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी ऐसे आयोजन सफल होते हैं। आम नागरिकों के सहयोग और सहभागिता से ही हम साहसिक पर्यटन को आर्थिक पर्यटन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद, परिवहन और अन्य सेवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे बढ़कर प्रशिक्षण लें, अपनी क्षमताओं को निखारें और उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर हब बनाने में योगदान दें।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के प्रति औपचारिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महोत्सव की सफलता सामूहिक योजना, सटीक क्रियान्वयन और आपसी समन्वय का परिणाम है। उन्होंने उल्लेख किया कि पर्वतीय भू-भाग, बदलते मौसम और नदी की धाराओं जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच गतिविधियों का संचालन प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे सभी संबंधित विभागों ने टीम भावना के साथ निभाया।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिभागियों का अनुशासन, तकनीकी दक्षता और सुरक्षा मानकों के प्रति सजगता आयोजन की गुणवत्ता को दर्शाती है। स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता ने यह साबित किया है कि नयार घाटी में साहसिक पर्यटन को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस आयोजन को दीर्घकालिक दृष्टि से विकसित करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसे और सुव्यवस्थित, तकनीकी रूप से सुदृढ़ तथा प्रशिक्षण-आधारित स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव भविष्य में प्रस्तावित पैराग्लाइडिंग संस्थान की आधारशिला सिद्ध होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास, कौशल विकास, पेशेवर प्रशिक्षण और स्थायी रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

फेस्टिवल के अंतर्गत माउंटेन बाईकिंग (एमटीबी) पुरुष वर्ग में प्रज्ज्वल ने प्रथम, नीरज भण्डारी ने द्वितीय तथा हिमांशु डबराल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में संध्या मौर्य ने प्रथम, वंदना सिंह ने द्वितीय और वर्णाली ने तृतीय स्थान हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिश एंगलिंग प्रतियोगिता में संजय परोरिया प्रथम, ट्रेवर होम्स द्वितीय तथा संजय पंचेस्वर तृतीय स्थान पर रहे।

क्याकिंग स्लालम स्पर्धा में अमर सिंह ने प्रथम, दमन सिंह ने द्वितीय तथा मनीष सिंह रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्प्रिंट स्पर्धा में भी अमर सिंह प्रथम, अमन सिंह द्वितीय और मनीष सिंह रावत तृतीय स्थान पर रहे। पैराग्लाइडिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में मोहर सिंह ने प्रथम, मनीष उप्रेती ने द्वितीय तथा अक्षय कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। टीम इवेंट में एडवेंचर जोन प्रथम, फ्लाई वारकला द्वितीय और पाजू भीमताल तृतीय स्थान पर रहे। राइजिंग स्टार पुरस्कार शीतल ठाकुर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का संचालन मंजीत रावत ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रश्मि देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रिय देवी, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, उपजिलाधिकारी रेखा आर्य, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, परियोजना प्रबंधक ग्रामोत्थान कुलदीप बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली पूनम उछोली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

होली हमारी समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक : मुख्यमंत्री

पथ प्रवाह, हल्द्वानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, परंपराएं और पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान के मूल आधार हैं। होली रंगों और उल्लास का त्योहार है, जो अपनों के साथ ही पूर्णता पाता है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि खटीमा उनका घर है और यहां के लोग उनका परिवार हैं। अपने परिवारजनों के बीच आकर उन्हें विशेष प्रसन्नता का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि जब बुजुर्ग उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं तो वह क्षण उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायी होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल, दियूरी खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता कर क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक कुमाऊँनी होली, शास्त्रीय होली एवं थारू होली गायन में जनसमूह के साथ सहभागिता करते हुए रंगोत्सव की खुशियों को साझा किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय ने पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होली मिलन जैसे आयोजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सद्भाव, समरसता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खटीमा सर्वधर्म समभाव की जीवंत मिसाल है और इसे 'मिनी इंडिया' के रूप में जाना जाता है। यहां सभी धर्मों एवं समुदायों के लोग प्रेम, सौहार्द और एकजुटता के साथ रहते हुए सभी पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं। आधुनिक परिवेश के बीच भी पारंपरिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर खटीमा, प्रदेश और देश की उन्नति के लिए कार्य करें तथा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ एक-दूसरे को गले लगाकर होली का पर्व मनाएं तथा संकल्प लें कि खटीमा को और बेहतर एवं आदर्श क्षेत्र बनाने हेतु निरंतर प्रयास करेंगे। आयोजन समिति की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महोत्सव सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ होली खेलकर उत्सव की खुशियों को आत्मीयता से साझा किया तथा सभी को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, उपाध्यक्ष अमित कुमार पांडे, महासचिव रमेश चंद्र जोशी, नंदन सिंह खड़ायत, गम्भीर सिंह धामी, दान सिंह रावत, सतीश भट्ट, डॉ. नवीन भट्ट, जीवन धामी, जिला पंचायत सदस्य रीना कफलिया, सूरज धामी, किशन ज्याला, जीवन कार्की, मीनाक्षी ज्याला, संतोष चंद, चरणजीत राणा, माया जोशी, बबीता चंद, सचिन रस्तोगी, शेर सिंह सामंत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

एक नजर

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट उद्योग को मिली पुन: संचालन की अनुमति

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा स्थित मैग्नेसाइट उद्योग को उच्च न्यायालय से चार माह के लिए पुनः संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े लगभग 500 परिवारों के करीब 2000 लोगों को राहत एवं संतोष मिला है। लंबे समय से उद्योग बंद होने के कारण प्रभावित परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप उद्योग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) से सीटीओ (Consent to Operate) प्राप्त किया गया। इसके उपरांत उच्च न्यायालय ने उद्योग एवं उससे जुड़े श्रमिकों और परिवारों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए पुनः संचालन की अनुमति प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के संरक्षण, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन और स्थानीय रोजगार सृजन–तीनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर स्तर पर सकारात्मक पहल कर रही है।

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय में छात्राओं को किया जागरुक

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय ज्वालापुर में जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने छात्राओं को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के ?निर्देश पर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में एसपी सिटी और नोडल अधिकारी के अलावा क्षेत्राधिकारी व महिला सुरक्षा अधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक मनीष भंण्डारी कांस्टेबल जसरुद्दीन खान महिला कांस्टेबल पूनम सौरियाल कोतवाली ज्वालापुर द्वारा कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय ज्वालापुर में जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090/1091, 1098, 1930 साइबर अपराध से बचाव, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, किरायेदार सत्यापन आदि तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं/अध्यापकगणों को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें। पुलिस सदैव आपकी सहायता एवं सुरक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही आत्मरक्षा के सामान्य उपायों एवं सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में सुरक्षा एवं विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया की पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने की बात कही गई।

नमामि गंगे के तहत सख्त निर्देश: कचरा जलाने व प्लास्टिक फेंकने पर चालान

पथ प्रवाह, बागेश्वर। जनपद गंगा समिति की बैठक जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगर निकायों, जिला पंचायत एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने बागेश्वर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विनोद सिंह जीना को निर्देशित किया कि नगर में लंबित लेगेसी वेस्ट का निस्तारण आगामी छह माह के भीतर, अर्थात सितंबर तक शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को इस संबंध में विशेष कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गरुड़ नगर पंचायत एवं कपकोट नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों द्वारा लेगेसी वेस्ट की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जहां-जहां कचरा निस्तारण के बाद भूमि खाली हो रही है, वहां उस स्थान को पारिस्थितिक दृष्टि से उपयोगी स्वरूप–जैसे पार्क, उद्यान अथवा अन्य जनोपयोगी विकास कार्य–के रूप में विकसित किया जाए, विशेषकर कपकोट क्षेत्र में मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जाए। बैठक में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। प्रत्येक निकाय एवं ग्राम पंचायत से कुल परिवारों की संख्या तथा निर्मित सोख गड्ढों की संख्या का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिन गांवों में स्वच्छता की स्थिति बेहतर है, उन्हें मॉडल स्वच्छ ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाए तथा अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधानों को वहां से सीख लेने हेतु प्रेरित किया जाए, ताकि आपसी अनुभव साझा कर स्वच्छता में सुधार लाया जा सके। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिए है कि कचरा जलाने की घटनाओं पर सख्ती से जुर्माना लगाया जाए साथ में प्लास्टिक का अनुचित निस्तारण एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर चालान की कार्रवाई बढ़ाई जाए। सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हुए राजस्व में वृद्धि के उपाय करें तथा शत-प्रतिशत घरों को कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद में अवैध कचरा डंपिंग के हॉटस्पॉट्स की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता से समाप्त किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जनआंदोलन है।

नमामि गंगे के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी विभागों, निकायों एवं ग्राम पंचायतों को समन्वित प्रयास करते हुए समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रवर्तन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जनपद को स्वच्छ एवं पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न, अपर जिलाधिकारी एन एस नबियाल, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली बिल वृद्धि और स्मार्ट मीटर के विरोध में हरिद्वार में गरजा कांग्रेस का जनाक्रोश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

बिजली बिलों में कथित बेतहाशा बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जोरदार पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा गांव नूरपुर पंजनहेड़ी से शुरू होकर जगजीतपुर बिजली घर तक पहुंची, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। 'कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद' और 'भाजपा सरकार हाय-हाय' जैसे नारों के बीच कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए बिजली घर पहुंचे। यहां एसडीएम जितेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर बिजली बिलों की बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की गई।

12 महीने में 13 बिल भेजने का आरोप

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से आम जनता बेहद परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग 12 महीने में 13 बिल भेज रहा है और सरचार्ज की वसूली के लिए बिलिंग चक्र में हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कई अनियमितताएं व्याप्त हैं और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से 'निचोड़ा' जा रहा है। गणेया गोदियाल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करेगी।

'जनता पर थोपी गई स्मार्ट मीटर योजना' – हरीश रावत

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता जनता पर थोपी जा रही है। उन्होंने इसे जनविरोधी कदम बताते हुए कहा कि यह पदयात्रा जनता की आवाज और एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप ले रही है। हरीश रावत ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और प्रदेश की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनभावनाओं के साथ खड़ी है और हर स्तर पर जनता की लड़ाई लड़ेगी।

ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत

हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत पदयात्रा को नेतृत्व करते बोली कि भाजपा ने मूलभूत सुविधाओं से भी जनता को तरसा दिया है। बिजली बिल में लूट मचाई हुई है। जिसके चलते जनता पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही भाजपा को सबक सिखायेगी। कांग्रेस जनता के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है।

कई विधायक व वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

पदयात्रा में हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में स्थापित होंगे मॉडल सहकारिता गांवः डॉ. धन सिंह रावत

अध्ययन भ्रमण पर गुजरात जाएंगे विभिन्न समितियों के 50 सचिव

पथ प्रवाह, देहरादून।

प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के विस्तार को प्रत्येक जनपद में एक-एक मॉडल सहकारिता गांव स्थापित किये जायेंगे। इस योजना को धरातल पर शीघ्र उतारने को विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शनिवार को अपने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने संस्कृत गांव की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में मॉडल सहकारिता गांव विकसित करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने बताया कि इन गांवों में सहकारी बैंक, सीएससी सेंटर एवं सहकारी बाजार की स्थापना की जाएगी। सहकारी बाजार स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों एवं ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का

उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं सहकारिता आधारित आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना है। समीक्षा बैठक में डॉ रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहकारी समितियों के 50 सचिवों को अध्ययन भ्रमण हेतु गुजरात भेजा जाए। भ्रमण में विशेष रूप से शैशवावस्था में कार्य कर रही समितियों के सचिवों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे सफल मॉडलों का अध्ययन कर अपनी समितियों को सशक्त बना सकें। डॉ रावत ने कहा कि होली के पश्चात संयुक्त निबंधक, अपर निबंधक एवं प्रभारी अधिकारी अपने-अपने जनपदों में ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठकें करेंगे। घाटे में चल रही समितियों को उबारने के लिए ग्राउंड जीरो पर रणनीति बनाकर ठोस कार्ययोजना लागू की जाएगी।

विभागीय मंत्री ने सभी पैक्स एवं एपेक्स समितियों की नियमित बोर्ड बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों में शत-प्रतिशत नियुक्तियां आईबीपीएस (IBPS) के माध्यम से पारदर्शी ढंग से किए जाने तथा 15 मार्च तक भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की तर्ज पर प्रदेश में भी सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं एवं सफलताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय बोली-भाषा में करने के निर्देश दिए गए, ताकि सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। डॉ. रावत ने कहा कि मॉडल सहकारिता गांव प्रदेश में सहकारिता के सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समावेशी विकास का आधार बनेंगे और आने वाले समय में यह पहल ग्रामीण विकास की नई मिसाल स्थापित करेगी।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉक्टर इकबाल अहमद, निबंधक सहकारी समितियां डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एम पी त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल, सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान, बलवंत सिंह मनराल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

विधायक और जिलाधिकारी ने सब्जी मंडी के विस्थापन स्थल का किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। नगर क्षेत्र में प्रस्तावित सब्जी मंडी के विस्थापन के संबंध में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के नेतृत्व में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित सब्जी मंडी के लिए उपयुक्त स्थल हेतु पहले काली कमली धर्मशाला के पीछे स्थित संभावित स्थल का अवलोकन किया गया। इस दौरान वहां उपलब्ध भूमि की स्थिति, पहुंच मार्ग, जल निकासी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का पूरा जायजा लिया साथ ही प्रस्तावित स्थल पर मंडी स्थापित होने से स्थानीय यातायात व्यवस्था एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान सब्जी मंडी हेतु ज्ञानसू क्षेत्र में सिंचाई विभाग के कार्यालय के समीप स्थित भूमि का भी निरीक्षण किया गया। जहां उपलब्ध क्षेत्रफल, पार्किंग की संभावना, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की सुविधा तथा भविष्य में विस्तार की संभावनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित विभागों ने इन जगहों की भौतिक स्थिति, यातायात प्रबंधन, जनसुविधाओं एवं आवश्यक आधारभूत संरचना की उपलब्धता के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिये। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान सामने आये तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर जल्द अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी, सीओ जनक पंवार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि विजय कुमार, ईई लोनिवि रजनीश सैनी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शालिनी चित्रण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिलाओं की वैज्ञानिक सोच एक उत्प्रेरकः जिलाधिकारी प्रशांत आर्य

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में यू-कॉस्ट और लक्ष्य सोसाइटी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के मुख्य विषय ''विज्ञान में महिलाएं: कैटलाइजिंग विकसित भारत'' थीम पर आधारित कार्यशाला में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की वैज्ञानिक सोच एक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है।आज का युग विज्ञान और नवाचार का है जहां महिलाओं की भागीदारी केवल एक विकल्प ना होकर समाज की अनिवार्य जरूरत है। इसी क्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी इस थीम पर अपने प्रभावशाली विचार साझा किए। विद्यार्थियों ने अपने भाषण और प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया कि कैसे महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नवाचार और सामाजिक बदलाव में भूमिका अदा कर रही है। जिलाधिकारी ने युवाओं के इन प्रगतिशील विचारों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन को प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। डीएफओ डीपी बलूनी,डिप्टी कमांडर 12वी.बी आईटीबीपी डीसी लेखराज, महाविद्यालय से प्रोफेसर डॉ.महेंद्रपाल परमार, लक्ष्य सोसाइटी से विक्रम रावत, महाविद्यालय स्टॉफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पैंसों के विवाद में बबलू की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, देहरादून

थाना रानीपोखरी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के भीतर मिली युवक की हत्या की गुत्थी को दून पुलिस ने सुलझाते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की यह वारदात पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में अंजाम दी गई थी। घटना के बाद आरोपी शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया था। 26 फरवरी 2026 को थाना रानीपोखरी पुलिस को सूचना मिली कि नीम करौली मंदिर धारकोट के पास एक निर्माणाधीन मकान के अंदर एक व्यक्ति चित अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में मिले व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जौलीग्रांट अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। शव के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की।

27 फरवरी को मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने उसकी पहचान बबलू पुत्र रिक्खी राम, निवासी ग्राम जरही मोतीपुर, जनपद बहराइच (उत्तर प्रदेश) के रूप में की। शिनाख्त के बाद पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

मृतक के भाई की तहरीर पर थाना रानीपोखरी में मु0अ0सं0 19/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में बबलू के साथ मजदूरी करने वाले पप्पू साहनी पर हत्या का आरोप लगाया गया।

एसएसपी के निर्देश पर गठित हुईं टीमें

घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान पता चला कि नामजद आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी। पुलिस टीम ने 28 फरवरी 2026 को आरोपी पप्पू साहनी पुत्र रामशरण, निवासी वार्ड नंबर 7, बांक बैंक, बेगूसराय शहर (बिहार) को भूइयां मंदिर थानों रोड से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और बबलू धारकोट क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करते थे। बबलू मिस्त्री का काम करता था। 22 फरवरी की रात पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने बबलू के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। वार लगते ही बबलू बेहोश होकर गिर पड़ा।

आरोपी ने बताया कि उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल न होने पर वह घबरा गया। अगले दिन सुबह उसने शव पर कंबल डालकर कमरे में बाहर से ताला लगा दिया और फरार हो गया। घटना के बाद वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उपनिरीक्षक हरीश सती, प्रभारी थानाध्यक्ष रानीपोखरी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनवर सिंह नेगी, थाना रायवाला, अपर उपनिरीक्षक विजेन्द्र सिंह

उपनिरीक्षक राजकुमार, कोतवाली ऋषिकेश, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल शशिकांत

होली पर्व के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने दिया जनता को गिफ्ट, एसएसपी के नेतृत्व में ढूंढ निकाले 140 खोए फोन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार पुलिस ने होली पर्व के मौके पर उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया जिनके मोबाइल फोन गुम हो गए थे और उनके मिलने की आस वह खो चुके थे। पुलिस ने 140 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके स्वामियों को वापस लौटाकर होली का गिफ्ट दिया।

एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा जनपद पुलिस को ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी/खोए मोबाइल की बरामदगी हेतु गठित सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए थाना सिडकुल पुलिस ने इस्थ्यद्रकपोर्टल के माध्यम से खोये हुए 140 मोबाइल फोन की रिकवरी करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। शनिवार को एसएसपी नवनीत सिंह ने सिडकुल थाने में ये रिकवर किये गए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को अपने हाथों से सौंपे। बरामद मोबाइलों में से कुछ फोन बाहरी राज्यों से जनपद हरिद्वार में रोजगार के लिये आये सिडकुल स्थित कम्पनियों के कर्मचारियों आदि के तथा कुछ फोन स्थानीय निवासियों के हैं। जिनकी कीमत लगभग 35 लाख से अधिक आंकी गई। अपने खोये हुये मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड चुके पीडितों के चेहरों पर पुलिस के द्वारा अपने अथक प्रयासों से मुस्कान लायी गयी जिस पर जनता द्वारा हरिद्वार पुलिस के इस कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी। हरिद्वार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें कोई लावारिश मोबाइल फोन मिलता है तो उक्त मोबाइल को तत्काल अपने नजदीकी थाना/पुलिस चौकी में जमा करा दें। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष नितेश शर्मा, व03नि0 देवेन्द्र तोमर, हे0का0 विवेक यादव शामिल रहे।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com